AADHAAR

NAVBHARAT TIMES, Lucknow, 13.6.2017
Page No. 6, Size:(17.11)cms X (24.17)cms.

आधार और पैन मांगा तो घट गए 29 हजार टीचर

एकेटीयू की सख्ती से शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े की खुली पोल

Ranvijay.Singh1
@timesgroup.com

■ लखनऊ : पैन और आधार नंबर के साथ शिक्षकों का ब्योरा मांगा गया तो निजी इंजीनियरिंग और प्रबंधन कॉलेजों में शिक्षकों का वास्तविक ब्योरा 40 हजार से घटकर केवल 11 हजार रह गया। यानी डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विवि (एकेटीयू) से संबद्ध निजी कॉलेजों में कागजों पर करीब 40 हजार शिक्षक पढ़ा रहे हैं जबकि असल में केवल 11 हजार शिक्षक ही हैं। एकेटीयू की सख्ती के बाद इस बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। अब इन कॉलेजों में पढ़ा रहे शिक्षकों का भौतिक सत्यापन की योजना है। एकेटीयू की टीम कॉलेजों में जाकर वहां पढ़ा रहे शिक्षकों से मुलाकात करेगी और वहीं पर उनसे जुड़ी जानकारियां दर्ज भी की जाएंगी।

एकेटीयू ने निजी कॉलेजों में पढ़ा रहे शिक्षकों के सत्यापन और जानकारियों के मानक कड़े होने से कॉलेज मनमानी नहीं कर सकेंगे। एकेटीयू ने कॉलेजों में पढ़ा रहे शिक्षकों के पैन कार्ड को सेलरी और कॉलेज एफिलिएशन के दस्तावेजों के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। बैंक अकाउंट में ज्यादा सेलरी देकर, बाद में निकाल लेना अब मुमकिन नहीं होगा।

अब तक फर्जी दस्तावेज

इस साल कॉलेजों के एफिलिएशन से पहले ही शिक्षकों का ब्योरा मांगा गया था। करीब 40 हजार शिक्षकों का ब्योरा भेजा गया। शिक्षकों के पैन और आधार नंबर भी भेजने को कहा गया। कॉलेजों ने केवल 11 हजार शिक्षकों के पैन कार्ड और आधार नंबर ही मुहैया कराए। वीसी प्रो. विनय पाठक ने बताया कि अब शिक्षकों की नियुक्ति व उन्हें दिए जाने वाली सेलरी में गड़बड़ी नहीं होने दिया जाएगा।

सही पाई गई शिक्षकों की शिकायत

बीकेटी स्थित जिस इंजीनियरिंग कॉलेज के शिक्षकों ने सैलरी के नाम पर फर्जीवाड़े की शिकायत की थी, उसकी जांच पूरी हो गई। बीकेटी पुलिस ने अपनी रिपोर्ट सीएम के जन शिकायत पोर्टल पर अपलोड कर दी। इरा रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि शिक्षकों की शिकायत सत्य पायी गई है और कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई किया जाना सही प्रतीत होता है। शिक्षकों ने आरोप लगाया था कि कॉलेज उनके खाते में हर महीने 50 से 80 हजार रुपये भेजता है। उसमें से 20 से 40 हजार रुपये निकाल लिए जाते हैं। शिक्षक हैरान हैं कि बिना उनका बयान दर्ज किए, पुलिस ने रिपोर्ट कैसे तैयार कर ली। शिक्षकों ने बताया कि पुलिस रिपोर्ट पर गवाहों और जांच अधिकारी के दस्तखत में करीब 20 दिन का अंतर है। यानी पहले पुलिस ने मामला रफादफा करने के लिए सादे कागज पर प्रबंधन के मुताबिक रिपोर्ट तैयार करने का आश्वासन देकर दस्तखत करा लिया। मामला मीडिया में उजागर होने के बाद गरदन बचाने के लिए कॉलेज के खिलाफ रिपोर्ट लगानी पड़ी।

सभी शिक्षकों के पैन और आधार नंबर भी मंगवा लिए थे। इसके बाद आधे से ज्यादा शिक्षकों का वैरिफिकेशन ही नहीं हो पा रहा है। – प्रो. विनय पाठक, कुलपति, एकेटीयू

एकेटीयू खत्म करेगा निजी वेंडरों की डेटा'गीरी'

■ एनबीटी संवाददाता, लखनऊ: एकेटीयू ऑनलाइन हो रहे विश्वविद्यालयों में निजी वेंडरों की डेटागिरी को खत्म करेगा। इसके लिए शासन के निर्देश पर एकेटीयू सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक ई विश्वविद्यालय पोर्टल बनाने जा रहा है। इस पोर्टल के जरिए सभी विश्वविद्यालय अपनी प्रवेश, परीक्षा व परिणाम से जुड़ी गतिविधियां संचालित कर सकेंगे। यह व्यवस्था लागू होने के बाद स्टूडेंट्स से जुड़े डेटा के लिए विश्वविद्यालयों को निजी वेंडरों के आगे बेबस नहीं होना पड़ेगा।

सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक ई विश्वविद्यालय पोर्टल तैयार करने के लिए सोमवार को एकेटीयू से संबद्ध इंजीनियरिंग कॉलेज आईईटी में एक अहम बैठक हुई। इसमें एकेटीयू के अलावा बरेली, आगरा, कानपुर और गोरखपुर विवि के कुलपतियों और प्रतिनिधियों के अलावा आईटी विशेषज्ञों ने भी हिस्सा लिया। इसमें सभी विश्वविद्यालयों ने स्टूडेंट्स से जुड़े डेटा को लेकर वेंडरों की मनमानी पर चिंता जताई। इस पर एकेटीयू के कुलपति ने सभी को आश्वासन दिया कि ई विश्वविद्यालय पोर्टल लांच होने के बाद यह मनमानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।

ऑनलाइन हुए किसी भी विश्वविद्यालय के पास डेटा नहीं

लखनऊ विवि समेत प्रदेश के जितने भी विवि ऑनलाइन हुए हैं, उनमें से किसी भी विवि के पास डेटा नहीं है। सभी ने निजी वेंडरों की मदद से ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की है, लेकिन किसी का भी इन वेंडरों पर नियंत्रण नहीं है। हर साल डेटा सुरक्षित रखने के नाम पर भारी शुल्क भी वसूलते हैं।

वहीं केजीएमयू मरीजों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन निजी एजेंसी से करवा रहा था। एजेंसी बदलने की कवायद हुई तो वेंडर ने अपना सर्वर ही हटवा दिया और डेटा एक्सेस होना बंद हो गया। हालांकि इसके बाद एनआईसी के विशेषज्ञों ने इस एजेंसी से डेटा वापस कराया। निजी एजेंसी जो काम हर महीने आठ लाख रुपये फीस लेकर करती थी, वही काम अब एनआईसी मुफ्त में कर रही है।

अब तक यह विवि जिन वेंडरों से अपनी ऑनलाइन सुविधाएं चला रहे हैं, वे वेंडर डेटा को लेकर अपनी मनमानी करते हैं। ऐसा अब नहीं हो सकेगा। जल्द ही इस संबंध में काम शुरू हो जाएगा। – प्रो.विनय पाठक, कुलपति, एकेटीयू

मोबाइल पर भी मिल सकेगी जानकारी

ई विवि पोर्टल शुरू होने के बाद विश्वविद्यालयों की सारी जानकारी मोबाइल पर भी मिल सकेगी। एकेटीयू कुलपति प्रो.विनय पाठक ने बताया कि सॉफ्टवेयर "क्लाउड आधारित" होगा। क्लाउड पर होने के कारण सभी राज्य विश्वविद्यालय एक-दूसरे के डेटा का आसानी से देख और सत्यापित भी कर सकेंगे। प्रो. पाठक ने बताया कि यह पोर्टल भारत सरकार के "मेघराज क्लाउड" पर होस्ट किया जाएगा।